भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-86

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

उच्च शिक्षा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव

†86. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा में चैट-जीपीटी जैसे एआई-आधारित सॉफ्टवेयर की बढ़ती भागीदारी की चिंताओं को दूर करने के प्रयास किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को विनियमित करने के लिए नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारत सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरू की है। एनईपी 2020 में सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए प्रासंगिक चरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिज़ाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) आदि जैसे समकालीन विषयों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

एनईपी 2020 का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, डिजिटल बाज़ार का विस्तार, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय आदि जैसे तेज़ी से हो रहे बदलावों के कारण संभावित और चुनौतियों की पहचान करने हेतु अनुसंधान के एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना भी है।

तकनीकी शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने आईटी कार्यक्रमों में एआई से संबंधित विषयों को शामिल किया है।

मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी गैर-कंप्यूटर विज्ञान शाखाओं के लिए विशेष एआई पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं ताकि उनके क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को एकीकृत किया जा सके। वर्ष 2021 में, एआईसीटीई ने एआई और डेटा साइंस के लिए एक आदर्श पाठ्यक्रम तैयार किया। संकाय को नई तकनीकों से अवगत रखने में मदद करने के लिए, एआईसीटीई एआई और अन्य उभरते क्षेत्रों में संकाय विकास कार्यक्रम भी चला रहा है।

इसके अलावा, एआई ज्ञान और कौशल तक पहुँच में सुधार के उद्देश्य से, शिक्षा मंत्रालय के स्टडी वेब्स ऑफ़ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने आईआईटी, आईआईएससी जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा तैयार किए गए 110 से अधिक निःशुल्क एआई से संबंधित पाठ्यक्रम प्रदान किए हैं। अब तक, 41.2 लाख से अधिक छात्रों ने इन पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया है।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि के लिए 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ, स्वास्थ्य, दीर्घकालिक शहरों और कृषि पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना को भी मंजूरी दी है।

भारत सरकार ने 7 मार्च 2024 को "इंडियाएआई" मिशन शुरू किया, जो देश के विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की एक रणनीतिक पहल है। यह मिशन सात आधारभूत स्तंभों नामतः- इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर (आईएआईसी), इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (आईएडीआई), इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पर ध्यान केंद्रित करके भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

जहाँ एक ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यक्तिगत शिक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह कुछ चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, शिक्षा मंत्रालय के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम ने "शैक्षणिक एआई उपयोग में नैतिकता" पर एक समर्पित विषय प्रस्तुत किया है। यह पहल संकाय सदस्यों और शैक्षणिक नेताओं को प्रमुख नैतिक विचारों का अन्वेषण करने में सक्षम बनाती है, और उन्हें एआई को अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों में जिम्मेदारीपूर्वक और प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए तैयार करती है।

*****